मूल्य 1 रु.

वर्षः 10 - अंक : 193, मुंबई, शुक्रवार, 9 अक्टूबर, 2020 ■ RNI.NO. MAHHIN/2010/34146 ■ संपादकः दिलशाद एस. खान

दैनिक मुंबई हलचल

भारत सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त R

अब हर सच होगा उजागर

मरकज केस में...

मोदी सरकार को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मौजूदा दौर में बोलने की आजादी के अधिकार का गलत इस्तेमाल हो रहा, आप कैसे कह सकते हैं कि मरकज केस में खराब रिपोर्टिंग नहीं हुई?

सांवददाता

नई दिल्ली। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेसन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कमेंट किया है। अदालत ने कहा कि मौजूदा दौर में बोलने की आजादी के अधिकार का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। अदालत ने गुरुवार को तब्लीगी जमात की मीडिया रिपोर्टिंग के मामले की सुनवाई करते हुए ऐसा कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तब्लीगी मामले में मोटिवेटेड मीडिया रिपोर्टिंग के आरोपों पर केंद्र सरकार की खिंचाई की। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इस मामले में अदालत में आप जो रवैया दिखा रहे हैं, वैसा नहीं चलेगा। (शेष पृष्ठ 3 पर)

''सरकार बताए कि तब्लीगी जमात जैसे मामलों में मोटिवेटेड मीडिया रिपोर्टिंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए''

- सुप्रीम कोर्ट

जमीयत-उलेमा-हिंद ने मरकज मामले की मीडिया कवरेज को मोटिवेटेड बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इसमें कहा गया है कि मीडिया गैर-जिम्मेदारी से काम कर रहा है। रिपोर्टिंग में ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मुसलमान कोरोना फैलाने की मुहिम चला रहे हैं।

॥शुभ लाभ॥

MIX MITHAI

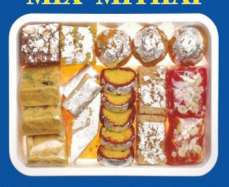

• मोतीचूर लड्डू • काजू कतरी • काजू रोल
• बदाम बर्फी • मलाई पेड़े • रसगुल्ले

MM MITHAIWALA

Malad (W) Tel. : 288 99 501

'धारावी मॉडल' ने दुनिया को दिखाई कोरोना से लड़ाई की राह

(समाचार पृष्ठ 3 पर)

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे

रामविलास पासवान

5 जुलाई 1946 - 8 अक्टूबर 2020

74 साल की उम्र में दिल्ली में निधन

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया। वे 74 साल के थे। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान के निधन पर कहा कि वो अपना दुख शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। मैंने अपना दोस्त खो दिया। रामविलास पासवान मोदी कैबिनेट में सबसे उम्रदराज मंत्री थे। (शेष पृष्ठ 3 पर)

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

हमारी बात

विरोध की सीमा

शाहीन बाग में करीब सौ दिन चले धरना-प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भले कुछ देर से आया हो, लेकिन स्वागतयोग्य है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ सुना दिया कि प्रदर्शनकारी अनिश्चितकाल के लिए किसी सार्वजनिक सड़क या जगह पर कब्जा नहीं कर सकते। कोई भी समूह या व्यक्ति प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक जगह को बाधित नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन किसी ऐसी जगह पर होना चाहिए, जहां भीड़भाड़ न हो। यह बात छिपी हुई नहीं है कि शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई संभव नहीं है। उससे जो व्यापक आर्थिक, सामाजिक क्षति पहुंची है, उसका आकलन और भी मुश्किल है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), एनआरसी और एनपीआर के विरोध में जब शाहीन बाग में प्रदर्शन हो रहा था, तब देश में माहौल काफी गरम था। इसके पक्ष व विपक्ष में समाज बंटा हुआ था। प्रशासन जब मजबूर हो गया था, प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिशें जब नाकाम हो गई थीं, तब सुप्रीम कोर्ट ने समाधान निकालने के लिए मध्यस्थों को भेजा था। कुछ दौर की बातचीत के बावजूद प्रदर्शनकारी मध्यस्थों की बात मानने को तैयार नहीं हुए। तब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोशिश हुई थी कि धरना कहीं और स्थानांतरित हो जाए और शाहीन बाग की बाधित सड़क खुल जाए। सुप्रीम कोर्ट की वह कोशिश नाकाम हो गई थी, पर तब तक कोरोना का कहर टूटा और धरने को 24 मार्च को लॉकडाउन की शुरूआत में हटा दिया गया। धरना हटाने का काम प्रशासन ने किया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन खुद सार्वजनिक स्थानों को अवरोधों से मुक्त रखे, सिर्फ अदालत के कंधे पर बंदूक रखकर न चलाए। इसमें कोई शक नहीं, सड़क को प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल करने से बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी होती है और उनके अधिकारों का हनन होता है। जहां हम भारतीयों को विरोध-प्रदर्शन का अधिकार है, वहीं हमें सड़क और सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल का भी अधिकार है। अव्वल तो लोगों को विरोध-प्रदर्शन से लोकतांत्रिक ढंग से रोकना-समझाना शासन-प्रशासन का काम है, वहीं होने वाले प्रदर्शन से दूसरे लोगों की रक्षा करना भी उसका दायित्व है। शासन-प्रशासन को अपने स्तर पर ही ऐसे प्रदर्शनों का सही समाधान खोजना चाहिए। गौर करने की बात है, जब सरकार धरना को कहीं और स्थानांतरित करने या खत्म करने में नाकाम रही, तब सड़क खुलवाने के लिए अदालत में याचिका दायर करने की जरूरत पड़ी। यह जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। अदालत को ऐसे मामलों को सुलझाने में वक्त लगता है, क्योंकि कानूनी प्रावधान के तहत सबका पक्ष सुनने के बाद ही कोई फैसला संभव होता है। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के बाद सरकारों को ज्यादा सचेत रहना चाहिए। धरना-प्रदर्शन के प्रति ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। समय से पहले ही समस्या की सुनवाई करने में भलाई है। किसी विरोध के सड़क पर उतरने और समाज पर भारी पड़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए। लोगों और संगठनों को भी अच्छी नागरिकता और परिपक्व लोकतंत्र की मिसाल पेश करनी चाहिए। जहां यह देखना जरूरी है कि धरना-प्रदर्शन करने के अधिकार का दुरुपयोग न हो, वहीं इनसे दूसरों को होने वाली परेशानी के बारे में भी सोच लेना चाहिए।

घोटालों से जुड़े सवालों का इंतजार

आखिर 2जी घोटाले में क्या मिला? लंबे इंतजार के बाद इस सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बीते दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआइ और ईडी की अपीलों पर दैनिक आधार पर सुनवाई करने का आदेश दिया। 2जी घोटाला केस में दिल्ली हाई कोर्ट को इस आरोप की जांच करनी है कि क्या सीबीआइ की विशेष अदालत ने दस्तावेजी सुबूतों को नजरअंदाज किया और मौखिक गवाही पर भरोसा किया? विशेष अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 में मिली शक्ति का उपयोग क्यों नहीं किया?

ध्यान रहे कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में दिल्ली स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने 2017 में आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया था। इस पर बहुत हैरानी जताई गई थी, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया घोटाला मानकर 122 लाइसेंस रद कर दिए थे और जुमार्ना भी लगाया था। किसी केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट की समझ में इतना बड़ा फर्क क्यों आया? 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मुकदमे में ए राजा और कनिमोझी को दोषमुक्त करते हुए विशेष सीबीआइ अदालत ने 2017 में कहा था, कलाइनगर टीवी को कथित रिश्वत के रूप में शाहिद बलवा की कंपनी डीबी ग्रुप द्वारा 200 करोड़ रुपये देने के मामले में अभियोजन पक्ष ने किसी गवाह से जिरह तक नहीं की। कोई सवाल तक नहीं किया। याद रहे उस टीवी कंपनी का मालिकाना हक करुणानिधि परिवार से जुड़ा है। माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा कोई सवाल नहीं किया गया, क्योंकि शायद मनमोहन सरकार के कार्यकाल में सीबीआइ के वकील को ऐसा करने की अनुमति नहीं रही होगी, पर अदालत के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसे ही मौके के लिए धारा 165 का प्रावधान किया गया है। आखिर इस शक्ति का उपयोग क्यों नहीं किया गया, जबकि यह सूचना उपलब्ध थी कि इस घोटाले में 200 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप लगा है? इस केस का यह सबसे प्रमुख सवाल है। उक्त धारा के अनुसार, न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता लगाने के लिए या उनका उचित सुबूत प्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी साक्षी या पक्षकार से, किसी भी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न, जो वह चाहे पूछ सकेगा तथा किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने का आदेश दे सकेगा। न तो पक्षकार और न उनके अभिकर्ता हकदार होंगे कि वे किसी भी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी आक्षेप करें। वे ऐसे किसी भी प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी की न्यायालय की इजाजत के बिना प्रति परीक्षा करने के भी हकदार नहीं होंगे। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मुकदमे में ए राजा और कनिमोझी को दोषमुक्त करते हुए विशेष जज की ओर से यह भी कहा गया था कि मैं पिछले सात साल से पूरी तन्मयता के साथ कोर्ट में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बैठा रहा और इंतजार करता रहा कि सीबीआइ कोई ठोस सुबूत लेकर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला, जो आरोपितों के अपराध को साबित करता हो। फिर चाहे वह कट ऑफ डेट को फिक्स करने की बात हो या पहले आओ पहले पाओ नीति के विरूपण का मामला हो। ऐसी टिप्पणियों के बाद ही यह कहना शुरू किया गया कि इस मामले में तो कुछ था ही नहीं। इसी तरह बोफोर्स घोटाले के बारे में भी कांग्रेस के कई बड़े-छोटे नेताओं ने लगातार यही कहा कि बोफोर्स घोटाला मीडिया की उपज था। आमतौर पर ऐसी बातें अधूरी जानकारी के आधार पर की जाती हैं, क्योंकि जब मामले को उनकी तार्किक परिणति तक पहुंचने ही नहीं दिया गया तो कैसे कहा जाए कि किसी घोटाले में क्या मिला? कम ही लोगों को मालूम है कि बोफोर्स मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामला विचाराधीन है। याद रहे कि 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जब बोफोर्स कांड के आरोपितों को दोषमुक्त करार दे दिया तो तत्कालीन मनमोहन सरकार ने उस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील तक नहीं की। प्रणब मुखर्जी ने तो यह तक कह दिया था कि चूंकि किसी अदालत ने इसे घोटाला नहीं कहा है, इसलिए इसे आधिकारिक तौर पर घोटाला नहीं कहा जा सकता है, पर वकील अजय अग्रवाल की लोकहित याचिका पर जब कभी सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा तो उसके सामने एक महत्वपूर्ण तथ्य आएगा। उस पर उसे अपनी राय बनानी होगी। दरअसल जिस मामले को निराधार मानकर दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपितों को दोष मुक्त कर दिया था, उसी घोटाले में मिले दलाली के पैसों पर भारत सरकार के आयकर महकमे ने आयकर वसूले। याद रहे कि भारत सरकार के आयकर न्यायाधिकरण ने कहा था कि ओत्तावियो क्वात्रोची और विन चड्ढा को बोफोर्स की दलाली के 41 करोड़ रुपये मिले थे। दलाली के ये पैसे भारत सरकार के खजाने से ही दिए गए थे। लिहाजा ऐसी आय पर भारत में उन पर टैक्स की देनदारी बनती है। आयकर विभाग ने दक्षिण मुंबई स्थित विन चड्ढा के फ्लैट को 12 करोड़ दो लाख रुपये में नीलाम कर दिया था। दूसरे दलाल क्वात्रोची को तो दलाली के पैसे स्विस बैंक की लंदन शाखा से निकाल लेने की सुविधा तत्कालीन मनमोहन सरकार ने प्रदान की थी।

नगा स्वायत्तता बनाम अखंड भारत

नगा शांति वार्ता का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (आइएम) के महासचिव ने मांग की है कि नगा शांति वार्ता किसी तीसरे देश में आयोजित की जाए। चूंकि एनएससीएन (आइएम) ग्रेटर नगालिम को एक पृथक देश के रूप में देखता है, अतः उसने प्रधानमंत्री कार्यालय से अपनी इस मांग का जवाब मांगा है और साथ ही नगालैंड में नृजातीय समुदायों द्वारा किए जाने वाले विप्लव को दूर करने के लिए नगा शांति वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्यक्ष भागीदारी की मांग भी की है। इन सभी मांगों के पीछे मुख्य व्यक्ति मुइवा हैं, जो स्वघोषित नगा सरकार के मुखिया हैं और पिछले कुछ दिनों में नगा पृथकतावाद से जुड़े मामलों पर अधिक सक्रिय हुए हैं।

उनका मानना है कि उनका समूह नगा समस्या को भारत के आंतरिक कानून व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में देखता है। मुइवा ने हाल ही में एक बार फिर से भारत सरकार और नगा विद्रोही समूहों के बीच 2015 में हुए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का हवाला देते हुए पृथक नगा संविधान, झंडे, राज्य चिन्ह या प्रतीक की मांग की है। ऐसे में किसी तीसरे देश में शांति वार्ता की मांग के संबंध में यह याद रखा जाना चाहिए कि भारत सरकार के प्रतिनिधि विद्रोही नगा नेताओं से विदेशों में मिलते रहे हैं और उन्हें शांति के रास्ते पर लाने के लिए कोशिश करते रहे हैं। यहां तक कि पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री रहते हुए नगा विद्रोहियों से फ्रांस में मिले थे, जबकि प्रधानमंत्री रहते हुए एचडी देवेगौड़ा की भी विद्रोहियों से मुलाकात स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुई थी।

पिछले सात दशकों से नगा अलगाववाद का मुद्दा भारतीय संघ की संप्रभुता और अखंडता पर एक प्रश्न चिन्ह के रूप में उपस्थित रहा है। केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए कभी सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के प्रावधानों को आजमाया तो कभी नगा विद्रोही गुटों एनएससीएन (आइएम) और एनएससीएन (खापलांग) को प्रतिबंधित समूह घोषित किया और कभी प्रतिबंध की समयावधि को बढ़ाया।

देश के संविधान ने अपने तरीके से पांचवीं अनुसूची और अनुच्छेद 371ए के जरिये नगालैंड की सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता के प्रावधान किए। अनुच्छेद 371ए को संविधान में 13वें संशोधन के बाद 1962 में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद नगालैंड के लिए विशेष प्रावधान करता है। इसके मुताबिक भारतीय संसद नगालैंड की विधानसभा की मंजूरी के बिना नगा समुदाय से जुड़ी हुई सामाजिक परंपराओं, पारंपरिक नियमों व कानून द्वारा किए जाने वाले न्यायों और नगाओं की भूमि संबंधी मामलों में कानून नहीं बना सकती है।

दैनिक
मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

समाचार

मुंबई, शुक्रवार
9 अक्टूबर, 2020

'धारावी मॉडल' ने दुनिया को दिखाई कोरोना से लड़ाई की राह

डब्ल्यूएचओ के बाद वर्ल्ड बैंक भी हुआ मुरीद

संवाददाता

मुंबई। एशिया के सबसे बड़े स्लम के रूप में पहचाने जाने वाले धारावी में भले ही कोरोना काल की शुरूआत में संक्रमण को लेकर चिंता की स्थितियां दिखी हों, लेकिन अब यह इलाका पूरी दुनिया में कोरोना से लड़ाई का आदर्श मॉडल बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाद अब विश्व बैंक ने मुंबई के धारावी में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की है। विश्व बैंक ने कहा कि समस्या के अनुरूप समाधान निकालने और सामुदायिक स्तर पर सहभागिता की वजह से ही धारावी में संक्रमण को फैलने से रोकने

में कामयाबी मिली। विश्व बैंक ने अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट में कहा कि मई में संक्रमण के मामले सर्वाधिक थे, जो आवश्यक रूप से उठाए गए कदमों के कारण तीन महीने बाद जुलाई में बीस प्रतिशत तक कम हो गए। विश्व बैंक ने 'गरीबी एवं साझा समृद्धि' नामक अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुंबई में अधिकारियों ने धारावी में बुखार और ऑक्सीजन के स्तर में कमी वाले मरीजों की बड़े स्तर पर जांच करने की रणनीति के तहत प्रयास किए। लोगों को इस जांच अभियान में शमिल किया। यही नहीं प्राइवेट अस्पतालों के कर्मचारियों को भी तैनात किया, जिससे वायरस को तेजी से फैलने से रोका जा सका।

दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में से एक: बता दें कि धारावी दुनिया की सबसे बड़ी स्लम एरिया में से एक है। यह ढाई किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैली है। धारावी में करीब आठ लाख लोग रहते हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 11 मार्च को सामने आया था। धारावी में एक अप्रैल को कोरोना का पहला मामला सामने आया था।

10 और 11 अक्टूबर को बारिश की संभावना

मुंबई। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हुए मौसम में बदलाव का असर आगामी कुछ दिनों में मुंबई में दिखेगा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार 10 और 11 अक्टूबर को मुबई और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही, 15 और 16 अक्टूबर को मुंबई, उपनगरों में अच्छी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। मौसम का आकलन करने वाली संस्था स्काइमेट के वॉइस प्रेसिडेंट महेश पलावत के अनुसार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र तैयार हुआ है। इस कारण मध्य महाराष्ट्र में निम्न दबाव की रेखा तैयार हुई है। इस कारण 10 और 11 अक्टूबर को मुंबई में हल्की बारिश और 15 और 16 अक्टूबर को मुंबई में अच्छी बारिश हो सकती है।

मास्क–सेनिटाइज की कीमतें सरकार तय करेगी

मुंबई। सरकार अब मास्क और सेनिटाइज की कीमतें निर्धारित करेगी। एन-95 मास्क 19 से 50 रुपये और दो-तीन लेयर वाले मास्क तीन-चार रुपये में मिलेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दावा किया कि मास्क की कीमतें तय करने का महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा। मास्क

अनिवार्य करने के बाद से मास्क की कीमतें बढ़ने लगीं। ऐसे में सरकार ने मास्क और सेनिटाइज की कीमतें तय करने के लिए एक समित का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना के खौफ से एन-95 मास्क 175 रुपये से 250 रुपये तक बिकने लगा।

महाराष्ट्र सरकार ने चीनी उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए की बैठक, पवार भी हुए शामिल

मुंबई। महाराष्ट्र सहकारिता विभाग ने राज्य में चीनी उद्योग के समक्ष मौजूद समस्याओं पर चर्चा करने के लिए यहां बृहस्पतिवार को एक बैठक की। इस बैठक में भाग लेने वाले राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि इथेनॉल परियोजनाओं और चीनी मिलों को वित्तीय सहायता समेत कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई। इस बैठक में राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, सहकारिता मंत्री बालासाहेब पाटिल और जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल भी शामिल हुए। इस बैठक में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राज्य सहकारी बैंक के अधिकारियों एवं चीनी संघ के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। शरद पवार ने ट्वीट किया, हमने बैठक में इथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, चीनी मिलों के लिए वित्तीय मदद और चीनी मिलों को ऋण के पुनर्गठन के तीन मुद्दों पर मुख्यतः चर्चा की।

(पृष्ठ 1 का शेष)

मरकज केस में मोदी सरकार को फटकार

कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जूनियर अफसर के जरिए एफिडेविट पेश कर दिया। इसमें टालमटोल वाला जवाब है और तब्लीगी जमात मामले के दौरान खराब रिपोर्टिंग को लेकर कोई डिटेल भी नहीं है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा- आप कैसे कह सकते हैं कि खराब रिपोर्टिंग नहीं हुई थी? अदालत ने अब इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री से इस बात का डिटेल एफिडेविट मांगा है कि ऐसे मामलों में मोटिवेटेड मीडिया रिपोर्टिंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। जमीयत-उलेमा-हिंद ने मरकज मामले की मीडिया कवरेज को मोटिवेटेड बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इसमें कहा गया है कि मीडिया गैर-जिम्मेदारी से काम कर रहा है। रिपोर्टिंग में ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मुसलमान कोरोना फैलाने की मुहिम चला रहे हैं। इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहले जो एफिडेविट दिया, उसमें कहा गया था कि जमात के मुद्दे पर मीडिया को रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकते। केंद्र ने प्रेस की स्वतंत्रता का हवाला दिया था।

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे

पिता के निधन के बाद चिराग ने गुरुवार रात 8 बजकर 40 मिनट पर रामविलास पासवान और अपने बचपन की फोटो के साथ एक भावुक ट्वीट किया। मोदी ने रामविलास पासवान के निधन पर दुख जाहिर किया और कहा कि पासवान कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचे। वो एक असाधारण संसद सदस्य और मंत्री थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया है। रामविलास पासवान संसद के सबसे अधिक सक्रिय और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मेंबर रहे। वे दलितों की आवाज थे और उन्होंने हाशिये पर धकेल दिए गए लोगों की लड़ाई लड़ी। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए कठिन समय है। बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अकेले लड़ने का फैसला किया है। और, पिता रामविलास नहीं रहे। चिराग ने अपने पिता का अंतिम समय तक साथ नहीं छोड़ा। बीते दो महीने से, यानी जब से बिहार चुनावों की गहमागहमी शुरू हुई, तब भी चिराग पिता के पास दिल्ली में मौजूद रहे। जब पासवान की तबियत बिगड़नी शुरू हुई, उसके बाद से चिराग किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं गए। एक बार दिल्ली के महावीर मंदिर गए, जहां उन्होंने पिता के लिए प्रार्थना की। बिहार चुनाव की सरगर्मी के बावजूद उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया। इंटरव्यू नहीं दिया और ना मीडिया में बयानबाजी की। लगातार अस्पताल और घर के बीच ही दौड़ते रहे। पार्टी की अहम बैठकों में भी केवल मौजूदगी के लिए पहुंचे। सोशल मीडिया के जरिए समर्थकों को पिता की बीमारी और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी देते रहे। रामविलास पासवान 11 सितंबर को अस्पताल में भर्ती हुए थे। एम्स में 2 अक्टूबर की रात को उनकी हार्ट सर्जरी की गई थी। यह पासवान की दूसरी हार्ट सर्जरी थी। इससे पहले भी उनकी एक बायपास सर्जरी हो चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिराग पासवान को फोन कर केंद्रीय मंत्री के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। रामविलास पासवान ने अस्पताल में भर्ती होते वक्त 3 ट्वीट किए थे और कहा था कि वो चिराग के हर फैसले में साथ हैं।

कोरोना के दौरान चुनावी रैलियां होंगी

केंद्र ने 12 राज्यों में चुनावी रैली को दी मंजूरी

100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकेंगे, पहले 15 अक्टूबर तक रोक लगाई गई थी

संवाददाता

नई दिल्ली। बिहार चुनाव और अन्य 11 राज्यों में उप चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। अब इन 12 राज्यों में बड़ी चुनावी रैलियां हो सकेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है। पहले 15 अक्टूबर तक राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन केंद्र के आदेश के बाद अब ये तत्काल प्रभाव से शुरू की जा सकेंगी। अनलॉक 5 की गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 से 200 लोगों की मौजूदगी को मंजूरी दी थी। अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है।

रैलियों के लिए ये है गाइडलाइन

- रैली के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों को कोविड-19 से जुड़े नियमों का सही तरह से पालन करना होगा।
- एंट्री गेट पर सभी समर्थकों के हाथ सैनिटाइज कराने होंगे।
- रैली में उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जो फेस मास्क पहने होंगे।
- सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा।
- बंद स्थानों पर सभा के दौरान लोगों के बैठने की क्षमता के अनुसार 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग का होना जरूरी है।

इन राज्यों में होना है चुनाव: बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नगालैंड और ओडिशा में चुनाव होने हैं। इनमें बिहार में विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि अन्य राज्यों में कुछ सीटों पर ही चुनाव कराए जाएंगे।

कोरोना संकट के बीच इन देशों में भी चुनाव: कोरोना संकट के बीच भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में भी चुनाव हो रहे हैं। इनमें अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, कोरिया, बेलारुस, इजराइल, हॉन्गकॉन्ग और पोलैंड शामिल हैं। इन देशों में भी पब्लिक रैलियों को मंजूरी मिली हुई है।

पुणे पुलिस ने पकड़ा 20 करोड़ का एमडी ड्रग्स

अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

पुणे। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से पूरे बॉलीवुड में उथल पुथल का माहौल है। इस मामले की जांच के दौरान पुणे शहर में एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का पदाफांश हुआ है। देश में ड्रग्स पर पाबंदी होने के बाद भी सभी जगह पर यह बिकता है। बॉलीवुड में ड्रग का एंगल सामने आने के बाद पुणे शहर में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। जिसमें तकरीबन 20

करोड़ का एमडी ट्रक जब्त किया गया है। पुणे पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने चाकन इलाके के पास शेल पिंपल गांव से बेचने के लिए लाए गए 20 करोड़ के मेफेड्रान ड्रग्स को जब किया है। पुलिस के मुताबिक अब तक पुणे शहर में अब तक इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स नहीं पकड़ा गया था। पुलिस अब इस ड्रग्स के जखीरे के मालिक तक पहुंचने के लिए उसकी तलाश पूरी सरगर्मी से कर रही है। साथ ही यह नशे का सामान कहां पर और किसको किसको भेजा जाना था इसका भी पता लगाने में जुटी हुई है।

गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई: पुणे पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि कुछ लोग एमडी ड्रग्स को खरीदने और बेचने के लिए चाकन के शेल पिंपलगांव में इकट्ठा होने वाले हैं। जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर इस मामले में 5 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इनके पास से 20 करोड़ का एमडी भी पकड़ा गया। साथ ही पुलिस ने इनके पास से एक कार और 23 हजार रुपए नकद भी जब्त किए हैं।

हाथरस केस: पीड़ित परिवार की तरफ से दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

प्रयागराज। हाथरस के पीड़ित परिवार की तरफ से दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई पूरी होने के बाद डिवीजन बेंच ने अपना जजमेंट रिजर्व किया है। पीड़ित परिवार की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में तीन अहम बातें कहीं गई थीं। अवैध रूप से नजरबंद किए जाने का आरोप था, मिलने-जुलने और खुलकर अपनी बात कहने पर बंदिशें लगने की बात थी। असुरक्षित महसूस करते हुए दिल्ली जाने देने की इजाजत दिए जाने की मांग थी। पीड़ित परिवार का बड़ा आरोप था कि हाथरस में वो सुरक्षित नहीं हैं और दिल्ली जाना चाहते हैं।

यूपी सरकार ने किया विरोध

यूपी सरकार ने अर्जी का विरोध किया। सरकार की तरफ से कहा गया कि परिवार को अवैध रूप से बंदी नहीं बनाया गया है। परिवार के लोग जहां जाना चाहें और जिससे मिलना चाहें उनसे मिल भी सकते हैं और बात भी कर सकता हैं।

कोर्ट में दिया सहमति पत्र

सरकार ने परिवार का एक सहमति पत्र भी कोर्ट में दिया, जिसमें परिवार के लोगों ने कोई दिक्कत नहीं होने की बात कही है। जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस प्रकाश पाडिया की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान अदालत का सबसे ज्यादा फोकस दिल्ली जाने की इजाजत दिए जाने पर रहा। पीड़ित परिवार के छह सदस्यों और अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी।

करीब एक घंटे तक हुई सुनवाई

मृतक लड़की के पिता, मां, दादी, दो भाई और भाभी के साथ ही सुरेंद्र कुमार ने अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में पीड़ित परिवार के बड़े लड़के ने सुरेंद्र कुमार और वाट्सएप कर हाईकोर्ट से मदद कराए जाने की गुहार लगाई थी। करीब एक घंटे तक मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से ओपन कोर्ट में काशिफ रिजवी और जान अब्बास ने पक्ष रखा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े थे। यूपी सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने पक्ष रखा।

योगी जी को रेप से दिक्कत नहीं पर उसकी चर्चा से है: जयंत चौधरी

सहारनपुर। हाथरस मामले में राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) नेता जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के विरोध में आज जाट महापंचायत बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 'लोकतंत्र बचाओ' जाट महापंचायत हुई। इस पंचायत में सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। महापंचायत में जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के साथ ही किसानों के मसले पर भी चर्चा की गई। अपने हाथरस दौरे को लेकर जयंत चौधरी ने कहा, मैं हाथरस इसलिए गया क्योंकि चरण सिंह ने सिखाया कि कभी दबे-कुचले के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जिस बच्चे को घर में संस्कार मिलते हैं वो बड़ा होकर वही बनता है। मेरे खून में है कि किसी बेटी के साथ व्यभिचार हो तो उसके साथ खड़ा हो। गरीब परिवार है और

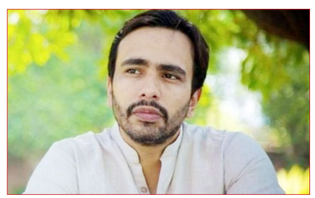

उसको अंतरराष्ट्रीय साजिश बता रहे हैं। कौन से संस्कार हैं कि बिना पिता के चिता में आग लगा दी गई। यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए जयंत ने आगे कहा, लोग जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि मुख्यमंत्री पूजा कर रहे हैं। योगी जी को भी धर्म के बारे में पता है पर छुपाने के लिए रात में ऐसा किया। गृह मंत्रालय ने कहा कि 2019 में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार यूपी में हुए। कहेंगे, तो बीजेपी का नेता कहेगा कि संस्कार सुधारो। समाज की बात तो है और पहले भी ऐसा चरण सिंह ने किया। जयंत ने अपना हमला जारी रखते हुए कहा, योगी जी को रेप से दिक्कत नहीं पर उसकी चर्चा से है, ये है सुशासन? भाइयों बहुत मार पड़ी, अलग-अलग तरह से पड़ी। एक भी शुगर मिल नहीं लगाया, कोल्हू भी नहीं लगाया एक भी। कहते हैं किसान की आय दोगुनी करेंगे, हुई क्या। गन्ना का बकाया दोगुना हो गया, 8500 करोड़ बकाया है आज।

इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन तेलंगाना टीम ने जरूरतमंद गरीबों को फलों के पैकेट किए प्रदान

संवाददाता/सैय्यद अल्ताफ हूसैन

इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन (ईरा) तेलंगाना की टीम के द्वारा कोरोना जैसी महामारी विपत्ति को लेकर जागरूकता अभियान वरंगल स्थल पर चलाया गया। अवसर पर इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन (ईरा) राज्य तेलंगाना अध्यक्ष अपरार्थी नाम नामपिल्लई, राज्य कार्यकारिणी अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल्ला और अन्य साथियों ने लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। उनकी जरूरतों के बारे में समझा और समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सांत्वना दी। उन्होंने सभी लोगों से बारी-बारी बातचीत करते हुए यथासंभव फलों के पैकेट दर्जनों प्रत्येक महिलाओं, युवतियों, और लोगों के बीच प्रदान की। ईरा तेलंगाना के पदाधिकारियों ने लोगों से कहां कि हम सभी पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों के बीच आकर भी जुड़ने का काम बखूबी करते हैं। चुंकी यह समाज हम सभी की एक जरूरत है। जिससे जुड़कर ही पत्रकारिता और जीवन के मूल्यों को जीवित रखा जा सकता है। हम लोगों ने आज के इस वरंगल

स्थल का निरीक्षण कर आम लोगों के जीवनशैली से रूबरू हुए हैं। जिससे ग्राउंड जीरो की भी बारे में जाना। इस संदर्भ में ईरा संगठन आगे सरकार के नुमाइंदों तक लोगों की तकलीफ, समस्याओं और हालात के बारे में भी जानकारी पहुंचाने का काम करेगी। कार्यक्रम में सहयोग देने वाले महिलाओं, समाजसेवियों, ग्रामीणों का ईरा टीम ने तहे दिल से धन्यवाद दिया। साथ ही लगातार ऐसे आयोजन लोगों को कुछ राहत पहुंचाने की बात कहीं है।

बुलढाणा हलचल

62 वर्षीय महिला ने कर्ज के कारण कुएं में कूदकर की आत्महत्या

महिंद्रा फायनेंस के अधिकारियों के खिलाफ जिला कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराई थी

बुलढाणा। जलगांव के जामोद तालुका में सुनगांव की 62 वर्षीय पार्वतबाई उखर्डा सोनोने 6 अक्टूबर से अपने घर में बिना किसी को बताए चली गई थी। इसलिए जब उन्हें ढूंढा गया, तो वे कहीं नहीं मिले, इसलिए उनके बेटे शिवदास सोनोन ने जलगांव पुलिस स्टेशन मिसींग शिकायत दर्ज किया। 7 अक्टूबर को सुबह 8.30 से 9 बजे के बीच शिवदास सोनवणे को फोन आया कि उनकी माँ का शव एक कुएँ में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तुरंत यहां आओ, इसलिए शिवदास सोनवणे बांडा पिंपल रोड पर किसान पांडुरंग वांडले के खेत में पहुंचा और शव की जांच करने के बाद, वो

शव उस की मां का ही निकला। इसलिए, शिवदास सोनोने जलगाँव पुलिस स्टेशन पहुंचा और रिपोर्ट में कहा कि वृद्ध पर महिंद्रा फाइनेंस का कर्ज था। जब महिंद्रा फाइनेंस के अधिकारी कर्ज की वसुली करने के आते धमकीयां देते थे। इस मामले की शिकायत जिला कलेक्टर के पास शनिवार, 3 अक्टूबर को की गई थी। शिवदास सोनोन ने शिकायत दर्ज कराई कि महिला को वित्त अधिकारियों से दिए गए धमकीया और अपमान के वजह से परेशान होकर आतमाहत्या करली ऐसी तक्रार वृद्ध के बेटे ने दी। उनकी शिकायत के अनुसार, जलगाँव पुलिस स्टेशन के पी. एस. आय. भारत बर्डे, पुलिस कांस्टेबल प्रेमसिंह पवार, पुलिस कांस्टेबल श्रीकृष्ण संदूक, होमगार्ड शिवाजी गोसावी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए खामगाँव रेफर कर दिया।आगे की जांच जलगांव जामोद पुलिस स्टेशन के पीएसआई सचिन वाकडे द्वारा की जा रही है।

45 वर्षीय व्यक्ति ने किया 10 वर्षीय लड़की पर अत्याचार, अंभोडा में हुई घटना, नागरिकों ने की आरोपी की पिटाई

बुलढाणा। जिले में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं।45 वर्ष के व्यक्ति ने 10 साल की लड़की के साथ जबरन यौन शोषण कि घटना 6 अक्टूबर की शाम को बुलडाणा तालुका के ग्राम अंबोडा गाँव में हुई। इस बीच, आरोपी का ईलाके के नागरिकों ने जबरदस्त पीटाई कि मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। मिली जानकारी के अनुसार 6 अक्टूबर को, बुलडाना ग्रामीण पुलिस ठाणे क्षेत्र के अंबोडा गाँव की 10 वर्षीय लड़की के माता-पिता, सोयाबीन सोगने के लिए खेत में गए थे। लडकी का पडोसी आरोपी संजय अर्जुन गायकवाड़ लड़की घर के सामने खेल रही आरोपी ने लडकी को घर के पिछे ले गया उसने उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। जब लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा तो लड़की चिल्लाने लगी, लड़की के दादा पेशाब करने के लिए उसी समय घर लौट आए. जब उन्होंने इस प्रकार को देखा। लडकी के दादा ने चिल्लाया उसी समय लड़की का भाई भागता हुआ आया, तो आरोपी संजय गायकवाड़ भाग गया लेकिन लोगों ने उसकी जबरदस्त पिटाई की। जैसे ही पीड़ित के माता-पिता को घटना के बारे में जानकारी मिली, वे घर आए और पीड़िता को बुलडाना ग्रामीण पुलिस स्टेशन, ठाणे ले गए और घटना को सुनाया। पुलिस तुरंत अंभोडा गांव पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पिटाई में जखमी होने पर उसे जिला सामान्य अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर ने उसे इलाज के लिए भर्ती कर लिया है। 7 अक्टूबर को बुलडाणा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में आरोपी संजय अर्जुन गायकवाड़ के खिलाफ धारा 376, 511 और धारा 7 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है और थानेदार सारंग नवलकर और दिलीप बोरसे द्वारा आगे की जांच की जा रही है।

हाथरस मामले के अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करके फांसी दीया जाए, महिला संघटन की मांग

बुलडाणा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक युवती से बलात्कार और नृशंस हत्या के खिलाफ बुलडाणा के स्त्री मुक्ती संघटना, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, सीटू संलग आंगणवाडी आणि आशा वर्कर महिला संघटना, ताराबाई शिंदे महिला जागृती संघटना, कृषी मल्टीपर्पज महिला फाऊडेशन अन्य महिला संगठन ने आज मानवता को शर्मसार करने के अमानवीय कृत्य के खिलाफ सार्वजनिक रूप से विरोध किया गया। पीड़ित परिवार के प्रति जिला पुलिस प्रशासन द्वारा दिखाई गई असंवेदनशीलता, उसके परिवार की सहमति के बिना पुलिस प्रशासन द्वारा

आधी रात को पीड़ित के शव का जबरन दाह संस्कार अपराधी का समर्थन करने का एक रूप है और यह योगी सरकार के लिए शर्म की बात है। इसकी निंदा की गई। उत्तर प्रदेश सरकार को बलात्कारियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उन्हें तुरंत फांसी देना चाहिए। इस संबंध में एक निवेदन महामहिम राष्ट्रपति को जिला अधिकारी एस। राममूर्ति के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को भेजा गया। निवेदन में कहा गया है कि राष्ट्रपति को इस निवेदन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और पीड़ित लड़की के परिवारों को सुरक्षा देनी चाहिए और उन्हें न्याय देना चाहिए।

रामपुर हलचल

चेहल्लुम का पर्व कोविड 19 की गाइड लाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया गया

संवाददाता नदीम अख्तर

टाण्डा (रामपुर)। गुरूवार को होने वाला चेहल्लुम का पर्व कोविड 19 की गइड लाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में रहकर ही मनाया गया। क्षेत्र में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई समाचार अशान्ति व्यवस्था को लेकर नहीं मिला है और न ही किसी भी जगह भीड़ भाड़ भी नहीं जुट सकी है कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार के दिशा निर्देशों का भी कड़ाई के साथ पालन किया गया उधर नगर पालिका परिषद द्वारा सम्पूर्ण नगर के अन्दर सफाई व्यवस्था बिजली पानी आदि की व्यवस्था की गई नगर के अन्दर कही भी किसी भी जगह गंदगी आदि के ढेर देखने को नहीं मिले साफ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान देते हुए पालिकाध्यक्ष मेहनाज जहाँ पति मकसूद लाला जी व अधिशासी अधिकारी राजेश सिंह राणा ने सम्पूर्ण नगर का दौरा कर निरीक्षण किया गया साथ कोविड 19 महामारी एवं उनसे बचाव के लक्षण भी बताये गये कोतवाल माधो सिंह विष्ट ने जगह जगह चेहल्लुम के स्थानों पर घूम कर जायजा लिया गया शान्ति पूर्णक ढंग से चेहल्लुम का पर्व मनाये जाने की भी अपील की गई इस मौके पर कोतवाल माधो सिंह विष्ट, एस. एस. आई मनोज कुमार, एस. आई. रामवीर सिंह, एस. आई सुरेश चन्द्र आदि पुलिस बल के साथ उपस्थित रहे।

नगर का मुख्य मार्ग की हालत खस्ताहाल, हर दिन होती है दुर्घटना

टांडा (रामपुर)। नगर का मुख्य मार्ग जो एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश उत्तराखड को जोड़ता है अक्सर मुख्य मार्ग में जगह जगह पर ऊबड़ खाबड़ गडढे होकर रह गये है कोई भी अन्जान व्यक्ति अपने वाहनों से उपरोक्त गड्ढों से गुजरता है तब अचानक अनहोनी की घटना घटित होकर रह जाती है अक्सर देखा गया कि दो पहिया वाहनों पर सवार महिलायें गड्ढों में मोटर साइकिल के प्रवेश होने के चलते अक्सर नीचे की ओर गिर है। जो गम्भीर अवस्था मे घायलावस्था की शिकार होकर रह जाती है। लगातार गड्ढों की मरम्मत आदि कार्य किये जाने की मांग पालिका अध्यक्ष मेहनाज जहां पती मकसूद लाला जी द्वारा व व्यापार मंडल के नगर उपाध्यक्ष मुहम्मद सलीम कसगर, मुहम्मद शरीफ अंसारी, द्वारा लगातार मांग की जाती है लेकिन अभी तक मुख्य मार्ग को गड्ढा मुक्त नहीं किया जा सका है। उधर नगर पालिका परिषद द्वारा जगह जगह गड्ढों में मिट्टी आदि का पटान कर घटना मुक्त कर दिया गया है लेकिन गड्ढों में मट्टी के चलते वाहनों के आवागमन के साथ साथ धूल का उड़ना शुरू होकर रह गया है जिससे दुकानदारों को भी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है लगातार प्रयासो के चलते विभाग चुप्पी साधे बैठा है। फिलहाल स्थिति ज्यो की त्यों बनी हुई है।

समस्तीपुर हलचल

मतदाता जागरूकता रैली निकाला गया

समस्तीपुर/हसनपुर। विधानसभा आम चुनाव 2020 को ले सभी बीएलओ ने प्रखंड मुख्यालय हसनपुर से हसनपुर बाजार,चीनी मिल चौक तक मतदाता जागरूकता रैली निकाला। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 140 हसनपुर विधानसभा सह प्रखंड विकास पदाधिकारी हसनपुर दुनिया लाल यादव ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। जागरूकता रैली के माध्यम से कोविड-19 के मद्देनजर सभी मतदान केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंस के दायरे में मास्क लगाकर विधान सभा आम चुनाव 2020 को ले बढ चढ कर मतदान में भाग लेने की अपील की गई। मौके पर निर्वाचन कर्मी शंभू प्रसाद,सुशांत यादव सहित सभी बूथों के संबंधित बीएलओ मौजूद थे।

विधायक शाहीन ने किया क्षेत्र का दौरा, जनता ने दिया जीत का आशीर्वाद

संवाददाता/जकी अहमद

समस्तीपुर। समस्तीपुर के स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने आज गुरुवार को विशनपुर पंचायत के दरियापुर, विशनपुर तथा खासखीदर में भ्रमण कर स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात किया तथा उनका कुशल क्षेम जाना। विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि क्षेत्र के चहुमुखी विकास को वे कृतसंकल्पित रहे हैं। वे हर एक समस्याओं के समाधान को अपने स्तर से इमानदार प्रयास किया है। कहा कि मैं समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्रार की जनता का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिसने मुझे लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंचाया। विधायक श्री शाहीन ने कहा कि हमने कभी जाति, धर्म/मजहब की राजनीति नहीं किया। इंसानियत की राह पर चलते रहे। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा हर पल समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र को सुन्दर बनाने के लिए समर्पित रहा है। क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि उनके द्वारा लगातार गरीबों के हित में कार्य किया गया है फलतः समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र विकास के रास्ते पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि शुरू से हमारा राजनीतिक लक्ष्य जनता की सेवा है। भेदभाव रहित सभी तबके का विकास हमारा संकल्प है। विशनपुर पहुंचने पर ग्रामीणों ने अपने विधायक का स्वागत किया तथा एक बार पुनः मौका देने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि हमें अपने विधायक पर गर्व है, इन्होने समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया है अतः क्षेत्र की जनता एक बार पुनः इन्हे अपने विधायक के रूप में देखना चाह रही है। इनकी जीत की हैट्रिक तय है। मौके पर जिला राजद प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर, राजद प्रखंड अध्यक्ष उमेश प्रसाद यादव, पंचायत अध्यक्ष विनोद महतो, पंचायत समिति सदस्य बिरजू महतो , पैक्स अध्यक्ष महेन्द्र महतो, पूर्व सरपंच भूषण महतो, पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुदेश्वर पासवान, छात्र राजद के जिलाध्यक्ष सतीश यादव, समाजसेवी गोपाल महतो, मो. वशीर अहमद, मो. आसिफ इकबाल, विजय कुमार राय, मनोज पासवान, ज्योतिष महतो, संजीव कुमार राय, ब्रजेश अधिकारी, मनोज दास, विजय शर्मा, संतोष राम आदि मौजूद थे।

वरिष्ठ नागरिक एवं निःशक्त मतदाता के लिए विशेष व्यवस्था

समस्तीपुर। जिले के ताजपुर प्रखण्ड निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में विधानसभा 133 समस्तीपुर एवं विधानसभा 135 मोरवा के सभी बीएलओ एवं सेक्टर पदाधिकारियों की एक अतिआवश्यक बैठक गुरुवार को डॉ0 लोहिया कपूरी विश्वेश्वर दास महाविद्यालय ताजपुर में की गई। बैठक में जानकारी देते हुए बीडीओ मनोज कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 में वरिष्ठ नागरिक 80 वर्ष से अधिक आयु पीडब्लूडी के निर्वाचकों एवं शारीरिक रूप से निःशक्त निर्वाचकों, जो मतदान करने के लिए बूथ पर जाने में असमर्थ हैं, वैसे निर्वाचक (मतदाता) के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा (सी) के अंतर्गत डाक मत पत्र की सुविधा की गई है। डाक मतपत्र सुविधा मुहैया कराने के लिए सभी बीएलओ अपने अपने बूथ क्षेत्र में 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचकों एवं शारीरिक रूप से निःशक्त निर्वाचकों की सूची तैयार कर तथा प्ररूप 12 (घ) में उनका विवरण जैसे विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र की संख्या, बूथ संख्या, नाम, पिता/पति का नाम,पूरा पता इत्यादि भर कर निर्वाचन कार्यालय को अवगत कराएंगे। ताकि वैसे मतदाता को डाक मत पत्र की सुविधा मुहैया कराया जा सके। जानकारी देते हुए बीएलओ शिद्धार्थ शंकर कुमार वर्मा ने बताया कि कार्य प्रगति के लिए सभी बीएलओ अपने अपने बूथ क्षेत्र में लग गए हैं। अविलम्ब प्रतिवेदन तैयार कर निर्वाचन कार्यालय को दी जाएगी।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

डायबिटीज की कड़वाहट बढ़ाता स्ट्रेस

भागती-दौड़ती जिंदगी में लाइफस्टाइल डिसीज का खतरा बढ़ता जा रहा है। हर उम्र और वर्ग के लोग इसके शिकार बन रहे हैं। डायबिटीज भी इन्हीं मुसीबतों में से एक है, जिसके पीड़ितों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। इस मुश्किल को बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारण है स्ट्रेस।

एक बीमारी, कई खतरे

डायबिटीज केवल एक बीमारी नहीं है। यह कई सारी मुसीबतों को आमंत्रण देने वाली एक स्थिति है। इसके कारण शरीर के विभिन्ना अंगों की कार्यप्रणाली पर बुरा असर पड़ने के साथ ही अंगों के क्षतिग्रस्त होने तक की आशंका हो सकती है। यही कारण है कि दुनिया भर में इसे लेकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है।

स्ट्रेस डालता है बुरा असर

दफ्तर, घर और यहां तक कि स्कूल और कॉलेज में तेज रफ्तार जीवन के कारण लोगों में तनाव जैसी स्थितियां आम तौर पर पनपने लगी हैं। मानसिक स्तर होने वाले यही बदलाव डायबिटीज के भी पैदा होने और फिर इसकी वजह से शरीर द्वारा गंभीर परिणाम झेलने की वजह बनते हैं। लंबे समय तक साथ रहने वाला स्ट्रेस शरीर की रक्त शर्करा के प्रबंधन की क्षमता को बाधित करता है। यदि ज्यादा समय तक यही स्थिति बनी रहे, तो समस्या बढ़ती चली जाती है।

लक्षण दशाएं स्ट्रेस

मानसिक, भावनात्मक तथा शारीरिक स्तर पर पड़ने वाला तनाव ही स्ट्रेस की स्थिति होती है। इसके कारण आप सिरदर्द, कंपकंपाहट, गुस्सा आना या व्यवहार में परिवर्तन, मूड स्विंग्स, पैनिक अटैक, तेज पसीना आना या भिंचे हुए जबड़े आदि जैसी अनुभूतियां कर सकते हैं। लंबे समय तक इसके बने रहने से शरीर इस तरह महसूस करता है मानो वह लगातार एक प्रकार के हमले से लड़ रहा हो। जब ऐसा होता है, तब शरीर में हार्मोन्स का स्तर बढ़ने लगता है और यह असंतुलन रक्त में शकर के संतुलन को गड़बड़ा सकता है।

डायबिटिक या सामान्य?

स्ट्रेस की यह स्थिति उन लोगों को तो दिक्कत देती ही है, जो पहले से डायबिटिक होते हैं। इसके अलावा वे लोग जिनमें अब तक शुगर के स्तर के बढ़ने जैसी स्थिति नहीं बनी है, वे भी इसकी जद में आ जाते हैं और डायबिटिक हो सकते हैं। वहीं स्ट्रेस के साथ अल्कोहल का सेवन, एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी की कमी, अनियमित खानपान तथा नींद में कमी मिलकर भी व्यक्ति को डायबिटीज की ओर धकेल सकती हैं।

करें परिवर्तन

स्ट्रेस की यह स्थिति तकलीफदायी न बने, इसके लिए प्रयास करें। डायबिटीज का सबसे अच्छा इलाज उसका सही प्रबंधन ही है। इसलिए कुछ खास बातों को हमेशा के लिए अपने जीवन का हिस्सा बना लें। इनमें शामिल हैं:

- ध्यान (मेडिटेशन) को अपनाएं
- सकारात्मक चीजों से जुड़ें
- बार-बार दुख देने वाले कारणों को याद न करें
- खुद को व्यस्त रखें
- गहरी सांस लेने व छोड़ने का अभ्यास नियमित करें
- नियमित व्यायाम को अपनाएं
- संगीत या अन्य क्रिएटिव चीजों के जरिए जीवन को सरल और प्रवाहमय बनाएं।

आप डायबिटिक हों, तब भी या न हों तब भी, इन चीजों को व्यवहार में जरूर लाएं। ये स्वस्थ बने रहने में आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी।

छोटा-सा मसल क्रैम्प और बड़ी-सी पीड़ा

मसल क्रैम्प यानी मांसपेशियों की ऐंठन या जकड़न बेहद आम समस्या है, जिससे लगभग हर व्यक्ति कभी-न-कभी प्रभावित होता है। शरीर की कोई मांसपेशी अचानक जकड़ जाती है, जिससे आप दर्द से सिहर उठते हैं। यूं तो कोई भी मांसपेशी इस प्रकार क्रैम्प की शिकार हो सकती है लेकिन अधिकांशतः पैरों की मांसपेशियों में ऐसा होता है।

क्यों होता है मसल क्रैम्प?

मसल क्रैम्प के कई कारण हो सकते हैं। इनमें प्रमुख हैं:

- रक्त संचार में गड़बड़ी
- कसरत या खेलकूद के दौरान मांसपेशियों पर अधिक जोर पड़ना
- डीहाइड्रेशन
- शरीर में मैग्नीशियम या पोटेशियम की कमी
- गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम की कमी
- रीढ़ की तंत्रिकाओं के दबने से भी टांगों में क्रैम्प की अनुभूति हो सकती है
- कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के तौर पर भी मसल क्रैम्प हो सकते हैं।

कैसे बचें क्रैम्प्स से?

क्रैम्प्स की समस्या से बचने के लिए आप कुछ साधारण उपाय अपना सकते हैं। डीहाइड्रेशन से हर हाल में बचें। इसके लिए अपनी शारीरिक गतिविधि को मद्देनजर रखते हुए समय-समय पर पानी पीते रहें। कुछ हल्का-फुल्का खाते भी रहें। इससे शरीर में पानी व खनिज की कमी नहीं होगी। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। यदि रात को नींद में पिंडलियों में क्रैम्प की समस्या होती है, तो सोने से कुछ पहले स्टेशनरी साइकल चलाने जैसा कोई हल्का व्यायाम करें। वहीं, यदि आपको लगता है कि किसी खास कसरत की वजह से आपको क्रैम्प की समस्या हो रही है, तो अपने एक्सरसाइज को रेजीम बदलें।

क्या करें जब क्रैम्प हो?

यूं तो क्रैम्प सामान्यतः कोई गंभीर समस्या नहीं होता लेकिन इसकी वजह से होने वाला तीव्र दर्द बुरी तरह व्यथित करके रख देता है। आप हल्का मसाज करके या थोड़ी स्ट्रेचिंग करके राहत पा सकते हैं। शुरूआती अवस्था में प्रभावित मांसपेशी पर सिकताव करने से लाभ हो सकता है। दर्द थोड़ा कम होने पर प्रभावित स्थान पर बर्फ लगाएं। अक्सर रात में सोते हुए अचानक पिंडलियों में जकड़न के कारण तीव्र पीड़ा होती है और व्यक्ति छटपटाते हुए जाग उठता है। ऐसे में सबसे आसान उपाय यह है कि आप खड़े हो जाएं और अपना वजन उस पैर पर डालें, जिसकी मांसपेशी में जकड़न आई है। यदि चलते-फिरते या कोई काम करते वक्त क्रैम्प हो आए, तो आप जो भी काम कर रहे हैं, उसे रोक दें और प्रभावित मांसपेशी को स्ट्रेच करें या फिर हल्के-से मसाज करें। अक्सर क्रैम्प का कारण डीहाइड्रेशन होता है। इसलिए पानी पीने से राहत मिल सकती है। मगर डीहाइड्रेशन का मतबल केवल पानी की कमी नहीं होता, इसमें खनिजों की भी कमी हो जाती है। इसलिए सॉल्ट टैबलेट या स्पोर्ट्स ड्रिंक भी लें।

कब जरूरी है डॉक्टर को दिखाना?

वैसे तो आप अपने स्तर पर ही कुछ सामान्य उपाय कर क्रैम्प से राहत व छुटकारा पा सकते हैं लेकिन कुछ मामलों में यह समस्या गंभीर रूप ले लेती है और तब डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। यदि जकड़न व दर्द बहुत अधिक हो, साधारण स्ट्रेचिंग से राहत न मिले, क्रैम्प लंबे समय तक बना रहे या बार-बार यह समस्या होती रहे, तो डॉक्टर के पास जाना ही बेहतर होता है। डॉक्टर विस्तृत परीक्षण करने के बाद थायरॉइड व गुर्दे के कार्य अथवा कैल्शियम/ पोटेशियम/ मैग्नीशियम मेटाबॉलिज्म की जांच हेतु टेस्ट कराने को कह सकते हैं। तात्कालिक राहत के लिए डॉक्टर कोई दर्दनिवारक दवा भी दे सकते हैं।

आपके पास मौजूद ये चीजें देती हैं संक्रामक बीमारियां, ऐसे करें बचाव

संक्रामक आदतें

क्या किसी से महज बात करने से ही उसकी समस्या आपके अंदर आ सकती है? क्या किसी का साथ आपको उसकी तकलीफ दे सकता है? जी हां, सिर्फ बीमारियां ही नहीं, बल्कि कुछ आदतें भी संक्रमण की तरह फैल सकती हैं। आइये जानते हैं ऐसी ही 7 अजीब संक्रामण चीजों के बारे में।

तनावग्रस्त सहकर्मी

अगर आपके साथ काम करने वाले शख्स का दिन तनावभरा है तो उससे बात करके या उसके आसपास रहकर आपको भी तनाव हो सकता है। दरअसल, ऐसी स्थिति में आपके उन हामोर्नों का स्तर बढ़ जाता है जो तनाव बढ़ाता है। इसलिए, ऐसे शख्स के संपर्क में आने के बाद खुद से संकल्पपूर्वक कहें, मुझे उसका तनाव नहीं चाहिए! उसके बाद गहरी सांस लें और वापस अपने काम

में लग जाएं

दोस्त की महंगी चीजें

अक्सर ऐसा होता है कि आपका दोस्त कोई महंगी चीज लाता है और उसे देखकर आपका भी मन होने लगता है कि वो चीज आपके पास भी हो। ऐसी स्थिति तभी खराब होती है जब कोई तुलना करने लगता है। अपने आपको याद दिलाएं कि खुशी वो चीजें हासिल करने में नहीं है, जो दूसरों के पास हैं।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

जब जूही चावला का हाथ मांगने उनके पापा के पास पहुंचे थे सलमान खान

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के अफेयर्स हमेशा ही चर्चा में रहे हैं। सलमान का नाम कई एक्ट्रेस से जुड़ा। संगीता बिजलानी, सोमी अली से लेकर ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, लूलिया वंतूर तक। लेकिन क्या आपको बता है कि सलमान खान कभी एक्ट्रेस जूही चावला से शादी करना चाहते थे और उनका हाथ मांगने वो उनके पिता के पास तक पहुंच गए थे। यह बात खुद सलमान खान ने एक चैट शो में बताई थी। सलमान ने कहा था, जूही बहुत स्वीट और बहुत प्यारी हैं। मैंने उनके पापा से पूछा था कि क्या आप जूही को मुझसे शादी करने देंगे? लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शायद उन्हें मैं पसंद नहीं आया। पता नहीं उन्हें क्या चाहिए था, शायद मैं जूही के लिए उन्हें सही नहीं लगा। सलमान और जूही कभी किसी फिल्म में लीड जोड़ी में नजर नहीं आए हैं। जब सलमान से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था, जूही मेरे साथ काम नहीं करना चाहतीं! हालांकि, इसके बाद साल 1997 में आई फिल्म दीवाना मस्ताना में सलमान और जूही का एक कोर्ट मैरिज सीन जरूर नजर आया था।

अर्जुन ने दी कोरोनावायरस को मात

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने आखिरकार एक महीने बाद कोरोनावायरस से जंग जीत ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी अपने फैंस के साथ शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना से ठीक होने के बाद वह कैसा महसूस कर रहे हैं? अर्जुन कपूर ने पोस्ट में लिखा, हाय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कोरोनावायरस टेस्ट निगेटिव आई है। मैं अब पूरी रिकवरी के बाद अच्छा महसूस कर रहा हूं और काम पर लौटने के लिए उत्साहित हो रहा हूं। उन्होंने शुभचिंतको का शुक्रिया करते हुए आगे लिखा, आप सभी की शुभकामनाओं और पॉजिटिव एनर्जी के लिए शुक्रिया। यह वायरस सीरियस है इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इसे सीरियसली लें। लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना का प्रभाव बड़ों और बच्चों दोनों पर है, इसलिए प्लीज हर समय मास्क पहनें। अर्जुन कपूर ने अपनी पोस्ट में बीएमसी को भी शुक्रिया कहा है। उन्होंने लिखा, शुक्रिया बीएमसी आपके सपोर्ट और हेल्प के लिए। उन सभी कार्यकताओं को सलाम जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी देख-रेख कर रहे है। हम आपके हमेशा कर्जदार रहेंगे।

क्या तीसरी बार शादी करने जा रहीं श्वेता तिवारी?

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी हल्दी लगाए नजर आ रही हैं। दुल्हन बने श्वेता तिवारी की ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। गालों पर हल्दी लगते ही श्वेता का चेहरा खिला-खिला नजर आया। आप सोच रहे होंगे श्वेता क्या तीसरी बार शादी करने जा रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल, टीवी शो मेरे डैड की दुल्हन में इन दिनों अंबर(वरुण बडोला) और गुनीत (श्वेता तिवारी) की शादी की तैयारी चल रही है। शादी के कई

फंक्शन और संगीत के बाद अब इस शो में श्वेता की हल्दी की रस्म हो रही है। गुनीत का रोल निभा रहीं श्वेता येलो रंग की मोनोटोन साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। अपने लुक में चार चांद लगाने के लिए उन्होंने खूबसूरत फ्लोरल ज्वैलरी पहनी थी। शूटिंग के दौरान अंबर (वरुण बडोला) प्लेन व्हाइट कुर्ता-पजामा पहने हुए थे। हल्दी की रस्म में उनका पूरा परिवार और उनके दोस्त खूबसूरत दुल्हन गुनीत को हल्दी लगाएंगे, जिनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान बिखरी हुई है।